Oil and Gas

| Publication: | The Times of India | Edition: | Chennai | Language: | English |
|---|---|---|---|---|---|
| Source: | Ram Sundaram | Supplement: | N/A | Page No: | 2 |

# Green nod for IOC's gas supply pipeline project

**FEEDER LINE** THE 120-KM PIPELINE ROUTE FROM ENNORE TO SALAVAKKAM

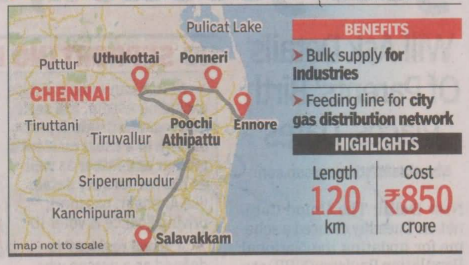


**BENEFITS**

- Bulk supply for industries
- Feeding line for city gas distribution network

**HIGHLIGHTS**

| Length | Cost |
|---|---|
| 120 km | ₹850 crore |

**Ram.Sundaram**
@timesgroup.com

**Chennai:** In a step towards ensuring piped natural gas supply to residents and industries in and around Chennai, the Union government's Expert Appraisal Committee (EAC) has approved Indian Oil Corporation's Ennore-Kancheepuram underground pipeline project.

The 120km pipeline will act as a feeder line for the upcoming city gas grid distribution (CGD) project, which aims at replacing LPG cylinders with piped natural gas (CNG) supply.

Till GCD becomes a reality, bulk supply to industries, which depend on natural gas, will be the primary role of IOC pipelines.

As more and more industries are shifting to natural gas from conventional sources like coal, demand for piped supply is witnessing a spike.

Earlier this year, IOC started operations along Ennore-Manali pipeline project. Industries like Chennai Petroleum Corporation Limited, Madras Fertilizers Limited and Tamil Nadu Petroproducts Limited have started receiving gas through these pipes, said an IOC official.

"The nod for Chennai-Kancheepuram project, costing ₹849 crores, indicates that adequate supply will soon be ensured to similar industries surrouding Chennai," he said.

According to the project design, 30 inch pipelines will be laid from Ennore LNG Terminal situated inside Kamarajar Port Limited, Ennore, to Salavakkam Village in Kancheepuram via Ponneri and Uthukottai.

Natural gas imported at the terminal will be transported to gas consumers along this route, including Hyundai Motors and Saint Gobain near Sriperumbudur.

As a portion of the proposed project (1.25 km) crosses the Coastal Regulation Zone (CRZ), IOC had submitted a proposal for EAC's clearance.

In its proposal, IOC said that though the pipeline is crossing the Kosasthalaiar river, horizontal drilling method (a trenchless technology) will be used to prevent ecological damage.

It has assured that depth of pipeline in CRZ area will be 10-15m below the scour depth of the water body.

Based on deliberations held in the meeting on November 29, EAC recommended CRZ clearance for the project given that IOC doesn't extract groundwater from the project site and no excavated material during construction was dumped in adjacent water bodies.

The project needs maximum of five kilo litres per day (KLD) of water and officials have decided to bring it through water tankers or public utility system.

| Publication: | Dainik Bhaskar (Hindi) | Edition: | New Delhi | Language: | Hindi |
|---|---|---|---|---|---|
| Source: | Bureau | Supplement: | N/A | Page No: | 1 |

## न्यूज ब्रीफ

# एक रिफिल पर 1000 किमी चलेगी सीएनजी बस

**नई दिल्ली** | पेट्रोलियम मंत्रालय ने मंगलवार को सीएनजी के इस्तेमाल से चलने वाली लंबी दूरी की पहली बस सर्विस की शुरुआत की है। महिंद्रा कंपनी की यह बस दिल्ली-देहरादून के बीच चलेगी। ऐसी 5 बसें खरीदी जा रही हैं। मंत्रालय के मुताबिक एक बार रिफिल करने के बाद यह बस 1,000 किमी की दूरी तय करेगी।

| Publication: | Hamara Mahanagar (Hindi) | Edition: | Mumbai | Language: | Hindi |
|---|---|---|---|---|---|
| Source: | Bureau | Supplement: | N/A | Page No: | 9 |

# अब सीएनजी की जगह बायोगैस का होगा इस्तेमाल

महानगर नेटवर्क

नई दिल्ली

**कंप्रेस्ड** बायोगैस (सीबीजी) से देश में सीएनजी की संपूर्ण मांग पूरी की जा सकती है। यह बात पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कही। अधिकारी ने कहा कि यदि बायोगैस का पूरी तरह से दोहन किया जाए, तो देश में हर साल 6.2 करोड़ टन सीएनजी के बराबर कंप्रेस्ड बायोगैस का उत्पादन हो सकता है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने अक्टूबर 2018 में सतत (सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवार्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन) पहल के तहत एक महत्वाकांक्षी योजना लांच की थी। इसके तहत सरकारी तेल एवं गैस कंपनियों को सीबीजी प्लांट लगाने के लिए व्यक्तिगत उद्यमियों से अभिरुचि पत्र आमंत्रित करना था। सतत कार्यक्रम में पूरे देश में 5,000 सीबीजी प्लांट लगाने का लक्ष्य रखा गया है। अनुमान है कि इससे 2023 तक हर साल 1.5 करोड़ टन सीबीजी का उत्पादन होगा। इस समूचे सीबीजी को सरकारी कंपनियां खरीद लेंगी। यदि 1.5 करोड़ टन सीबीजी उत्पादन का लक्ष्य हासिल हो जाता है, तो यह सीएनजी की मौजूदा सालाना खपत के 40 फीसदी हिस्से की पूर्ति कर सकता है। पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक कारोबारी साल 2018-19 में 4.4 करोड़ टन सीएनजी बिका था। कार्यक्रम के संचालन का जिम्मा इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, गेल और इंद्रप्रस्थ गैस को दिया गया है। मंत्रालय के एक निदेशक विजय शर्मा ने इन कंपनियों द्वारा सतत कार्यक्रम पर आयोजित एक रोड शो में कहा कि यदि सीबीजी का पूरा दोहन हो, तो तो हर साल करीब 6.2 करोड़ टन सीबीजी का उत्पादन हो सकता है। इससे पूरे देश में गैस की संपूर्ण मांग पूरी हो सकती है। योजना की घोषणा के वक्त पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था कि देशभर में सीबीजी प्लांट लगाने के लिए करीब 1.75 लाख करोड़ रुपए का निवेश करना होगा। गौरतलब है कि सरकार 2022 तक कच्चे तेल के आयात में 10 फीसदी की कमी करना चाहती है।

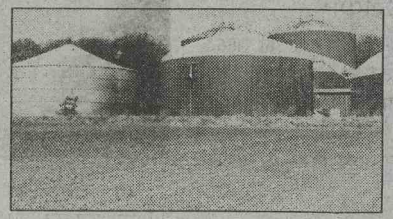

इसी समय सीमा में सरकार ने किसानों की आय भी दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है। सरकार को उम्मीद है कि सतत योजना से 75,000 लोगों को सीधे तौर पर रोजगार मिलेगा। साथ ही इस योजना से पांच करोड़ टन जैविक खाद भी बनेगा। शर्मा ने कहा कि परिवहन क्षेत्र में सीबीजी के इस्तेमाल से कचड़ा प्रबंधन, कार्बन उत्सर्जन में कमी और किसानों को अतिरिक्त आमदनी जैसे अतिरिक्त लाभ भी मिलेंगे।

| Publication: | Lokmat (Marathi) | Edition: | Mumbai | Language: | Marathi |
|---|---|---|---|---|---|
| Source: | Santosh Thakur | Supplement: | N/A | Page No: | 7 |

# सीएनजीवर आता एक हजार किमी चालेल बस

संतोष ठाकूर
लोकमत न्यूज नेटवर्क

**नवी दिल्ली :** दोन शहरांत आता मोठ्या प्रमाणावर सीएनजी बस धावताना दिसतील. पेट्रोलियम व पोलाद मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी मंगळवारी दिल्लीत या प्रकारच्या बसला हिरवा झेंडा दाखवून रवाना केले.

ही बस एकदा सीएनजी भरून घेतल्यावर ८०० ते एक हजार किमीपर्यंत चालेल. त्यासाठी बसच्या सिलेंडरमध्ये बदल केला गेला असून कार्बन स्टील सिलेंडर टाईप एकच्या जागी कंपोझिट टाईप फोरचे सिलेंडर लावले गेले आहे. हे सिलेंडर आधीपेक्षा ७० टक्के हलके आहे आणि त्यात एकावेळेस जास्त गॅस भरला जातो. त्या आधी टाईप एकच्या सिलेंडरमुळे सीएनजी बस मुख्य रु पात शहरांत वापरली जायची किंवा ट्विन सिटीत उपयोगात यायची. पण, जर बसला दोन शहरांत चालवले जात असेल आणि सीएनजी संपला तर प्रवाशांची गैरसोय व्हायची. बसमध्ये सीएनजी रि-फिलिंगचा प्रश्न निर्माण व्हायचा, असेही प्रधान म्हणाले.

यामुळे शहरांत स्वच्छ इंधनावर सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था वाढेल. त्यामुळे पर्यावरणावरही सकारात्मक परिणाम होईल. दिल्ली-एनसीआरमध्ये जवळपास ५०० सीएनजी पंप आहेत. तर एकट्या दिल्ली-एनसीआरमध्ये १२ लाख घरांत पाईपने स्वयंपाकाचा गॅस पोहोचवला जात आहे. प्रधान म्हणाले की, आम्ही आमच्या अर्थव्यवस्थेला गॅस आधारित बनवण्यासाठी सर्व पावले उचलत आहोत. त्यासाठी १०० अब्ज अमेरिकन डॉलरच्या गुंतवणुकीसाठी वेगवेगळे प्रकल्प येऊ घातले आहेत. आम्ही शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी व पर्यावरण संरक्षणासाठी देशात पाच हजार कॉम्प्रेसड बायोगैस प्लँट लावण्याचे काम करीत आहोत. त्याअंतर्गत तेल कंपन्या शेतकऱ्यांना एक ठराविक रक्कमेवर त्यांच्याकडील बायोगॅस विकत घेण्याचा करारही करील. पर्यावरण संरक्षणासाठी आम्ही बीएस-फोरवरुन थेट बीएस-६ वर जायचा निर्णय घेतला. एप्रिल २०२० पासून तो संपूर्ण देशात लागू होईल.

| Publication: | Yashobhoomi (Hindi) | Edition: | Mumbai | Language: | Hindi |
|---|---|---|---|---|---|
| Source: | Bureau | Supplement: | N/A | Page No: | 12 |

# ईंधन भराने के लिए बेहतरीन फास्टलेन

**मुंबई,** एजीएस का फास्टलेन ईंधन भरने का एक नया क्रांतिकारी तरीका है जो ईंधन स्टेशनों पर ईंधन भराने का बेहतरीन अनुभव प्रदान करता है। एक कैशलेस, कॉन्टैक्टलेस और पेपरलेस पेमेंट तकनीक, यह उन्नत रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक का लाभ उठाती है, जो प्रत्येक यात्रा के दौरान अविश्वसनीय ग्राहक अनुभव सुनिश्चित करती है। यह ग्राहकों की चिंता, असुविधाओं और तनाव बिंदुओं से सीधे निपटकर यह सुनिश्चित करता है कि ग्राहक बिना किसी परेशानी के ड्राइव कर सकते हैं, ईंधन भर सकते हैं और बाहर निकाल सकते हैं। यह व्यक्तियों और कॉरपोरेट्स / बेड़े को वाहन में भरी जाने वाली ईंधन की वांछित मात्रा को निर्धारित करने की अनुमति देता है, फ्युल गेज को शून्य पर रीसेट करता है, और यह सुनिश्चित करता है कि वे जितनी बार ईंधन भराते हैं, उसका भुगतान करते हैं। व्हीलर्स के लिए उपलब्ध, फास्टलेन फ्लीट मालिकों और व्यक्तियों के लिए आदर्श है। फास्टलेन वॉलेट के माध्यम से, पूरे लेनदेन को डिजिटल रूप से प्रबंधित किया जाता है, एजीएस प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित भुगतानों के माध्यम से, जो उपयोगकर्ता को नकदी या कार्ड तक पहुंचने के बिना बाहर ड्राइव करने की अनुमति देता है। इसकी डिजिटल और पारदर्शी भुगतान प्रक्रिया से चोरी का जोखिम कम हो जाता है। इसके अतिरिक्त, फास्टलेन ऐप उपयोगकर्ता को वास्तविक समय के आधार पर (ऑनलाइन रिपोर्टों के माध्यम से) ईंधन की खपत और प्रति वाहन खर्च पर नजर रखने और चोरी के जोखिम को कम करने में सक्षम बनाता है।

| Date | Headline | Publication | Edition | Page No. | Journalist | MAV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oil and Gas | | | | | | |
| 25 Dec 2019 | Green nod for IOC's gas supply pipeline project | The Times of India | Chennai | 2 | Ram Sundaram | 420959 |
| 25 Dec 2019 | CNG buses run 1000 km on one refill | Dainik Bhaskar (Hindi) | New Delhi | 1 | Bureau | 18450 |
| 25 Dec 2019 | Now biogas will be used instead of CNG | Hamara Mahanagar (Hindi) | Mumbai | 9 | Bureau | 104750.4 |
| 25 Dec 2019 | One thousand km of buses will now run on CNG | Lokmat (Marathi) | Mumbai | 7 | Santosh Thakur | 62088 |
| 25 Dec 2019 | The best refueling fastlane | Yashobhoomi (Hindi) | Mumbai | 12 | Bureau | 27632 |